उत्तराखंड उच्च न्यायालय ,नैनीताल

श्री न्यायमूर्ति एस.के. मिश्रा, ए.सी.जे.

और

श्री न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे, जे.

4 अप्रैल, 2022

ए.ओ. संख्या 36/2022

दिनेश ठाकुर. ...अपीलार्थी।

बनाम

साक्षी बंसल ... प्रतिवादी

अपीलकर्ता के वकील : श्री चंद्रशेखर जोशी और श्री गौरव कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के वकील : सुश्री दिव्या जैन और श्री मनीष लोहानी, विद्वान वकील।

पक्षों को सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:
(श्री एस.के. मिश्रा, ए.सी.जे.)

इस अपील में याचिकाकर्ता, माननीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून के समक्ष विविध में 2020 के केस संख्या 25 ने 17.12.2021 को अदालत द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 9 के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "संहिता" के रूप में संदर्भित) , संहिता की धारा 151 के साथ पढ़ें।

2. वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कार्यवाही शुरू की। इसे 2019 की सिविल कार्यवाही संख्या 437 के रूप में पंजीकृत किया गया था, और 14.11.2019 को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, वर्तमान अपीलकर्ता ने अन्य आवेदन दायर किया जिसमें विविध हैं। उसी की बहाली के लिए 2019 का आवेदन संख्या 74, लेकिन इस बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 31.12.2019 से 17.03.2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच, 31.01.2020 को, जब वह हिरासत में थे, पहली बहाली आवेदन माननीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।

3. अपीलकर्ता ने फिर से विविध दायर किया। 2020 का आवेदन क्रमांक 25, जिसमें से प्रथम बहाली आवेदन (2019 का क्रमांक 74) की बहाली के लिए वर्तमान अपील उत्पन्न होती है, जिसे 08.10.2020 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि बहाली को प्राथमिकता देने में तेरह दिनों की देरी हुई थी उक्त मामले में आवेदन, और कोई विलंब क्षमा आवेदन दायर नहीं किया गया था|

4. अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि दिनांक 17.12.2021 के आदेश के पैरा संख्या 9 में,. माननीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ने नोट किया है कि विविध 2019 के आवेदन संख्या 74 को 31.01.2020 को खारिज कर दिया गया था, और उसी की बहाली के लिए सीमा तीस दिन है, जो 01.03.2020 को समाप्त हो गई , कोई विलंब क्षमा आवेदन दायर नहीं किया गया है। माननीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून द्वारा यह फिर से नोट किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, 15.3.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि की सीमा को बाहर कर दिया गया है। फिर भी, माननीय न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदन विलम्बित अवस्था में दायर किया गया है।

5. दिनांक 17.12.2021 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 10 में, माननीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून ने माना है कि दूसरे बहाली आवेदन में, अपीलकर्ता ने उस मामले की संख्या का उल्लेख नहीं किया है जिसे बहाल किया जाना है। इसलिए, इन दो आधारों पर, बहाली आवेदन खारिज कर दिया गया है।

6. हमारी ओर से संहिता के आदेश 9 नियम 9 को उद्धृत करना उचित होगा। इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:-

"**9. डिफ़ॉल्ट रूप से वादी के विरुद्ध डिक्री नए वाद को वर्जित करती है।**

(1) जहां कोई वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतया या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी को उसी वाद हेतुक के संबंध में नया वाद लाने से रोका जाएगा। लेकिन वह बर्खास्तगी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि जब मुकदमे की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तो उसकी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था, अदालत बर्खास्तगी को रद्द करने का आदेश देगी। लागत के रूप में शर्तों या अन्यथा के रूप में यह उचित समझता है। और वाद की कार्यवाही के लिए एक दिन नियत करेगा।

(2) इस नियम के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि विरोधी पक्ष को आवेदन की सूचना तामील न कर दी गई हो।"

7. संहिता का उपरोक्त आदेश 9 नियम 9 एक परोपकारी प्रावधान है, जो उन व्यक्तियों के लिए एक उपाय प्रदान करता है, जिन्हें पर्याप्त कारण से अदालतों में पेश होने से रोका गया है, उन मामलों की बहाली के लिए जिन्हें खारिज कर दिया गया है और उन्हें अलग करने के लिए बर्खास्तगी का आदेश।

8. इसके अलावा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य पारिवारिक विवादों को तय करने के लिए एक बेहतर तंत्र बनाना है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रदान करता है कि पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ सुलह पर जोर दिया जाना चाहिए और सामाजिक रूप

से वांछनीय परिणाम प्राप्त करना चाहिए और प्रक्रिया और साक्ष्य के कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट (1974) में इस बात पर भी जोर दिया था कि परिवार से संबंधित विवादों से निपटने के लिए अदालत को सुनवाई शुरू होने से पहले समाधान के लिए एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह भी पता चलता है कि ऐसी सिफारिशों के बावजूद, अदालतें पारिवारिक विवादों को अन्य नागरिक मामलों की तरह ही निपटा रही हैं और वही प्रतिकूल दृष्टिकोण प्रचलित है।

9. इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के तहत कार्यवाही को प्रतिकूल विवाद के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि न्यायालय को पक्षों के बीच समझौता करने के लिए सक्रिय होना चाहिए, ताकि सामाजिक रूप से स्वीकार्य परिणाम प्राप्त हो सके।

10. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि माननीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून द्वारा दिए गए आदेश में की गई टिप्पणी कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों के विपरीत प्रतीत होती है, और इसलिए, हम आगे की राय रखते हैं कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए। माननीय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून ने इस मामले में तथ्यों और कानून की व्याख्या करने में बहुत ही तकनीकी और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

11. इस मामले को देखते हुए दिनांक 17.12.2021 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। 2020 के दूसरे बहाली आवेदन संख्या 25 की अनुमति है। हम 2019 के पहले बहाली आवेदन संख्या 74 की अनुमति देने के लिए भी विवश हैं, और हम मामले को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन की योग्यता पर विचार करने के लिए वापस भेज देते हैं। पक्षकारों को इस आदेश की नकल 2 मई, 2022 तक कुटुम्ब न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

12. वर्तमान अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

13. इसकी अगली कड़ी में, सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।

14. इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति पक्षकारों को नियमानुसार जारी की जाए।

———

एस.के. मिश्रा, ए.सी.जे.

——

आर.सी. खुल्बे, जे.

दिनांक: 4 अप्रैल, 2022
राठौर